



करेंट अफेयर्स

मध्य प्रदेश

फरवरी

(संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश

➤ भोपाल में पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का हुआ रंगारंग आगाज	3
➤ कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिये एम.पी. ट्रांसको ने ऊर्जाकृत किया रेलवे ट्रेक्शन फीडर	3
➤ गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एन.सी.सी.कैडेट्स हुए सम्मानित	4
➤ खेलो इंडिया बाक्सिंग में मेजबान मध्य प्रदेश ने जीते 13 पदक	4
➤ कैनोए स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने दो स्वर्ण पदक जीते	5
➤ मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक की 20 शाखाओं का किया शुभारंभ	5
➤ सुराज नीति-2023	6
➤ मध्य प्रदेश की मंत्रि-परिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय	7
➤ एआईएफ योजना में मध्य प्रदेश	8
➤ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022: मध्य प्रदेश ने तीन स्वर्ण और एक रजत जीता	8
➤ मध्य प्रदेश ने रोइंग में जीते दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक	8
➤ मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की SATTE 2023 में भागीदारी	9
➤ मध्य प्रदेश ने हॉकी में जीता स्वर्ण और रजत पदक	9
➤ राष्ट्रीय मेरिट कम मीस छात्रवृत्ति के आधार पर जिलों एवं विकासखंड की रैंकिंग तय	9
➤ चर्चा में क्यों ?	9
➤ इंदौर का ग्रीन ब्रांड बना नंबर-1	10
➤ खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2022 में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान	10
➤ अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ	11
➤ इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर यश टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ	11
➤ राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित	12
➤ जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा इस्लामनगर	12
➤ मुख्यमंत्री ने कूनो में 12 और चीतों को छोड़ा	13
➤ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्वपूर्ण निर्णय	13
➤ मध्य प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिये उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन	15
➤ मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डेवेलपमेंट कोर ग्रुप का गठन	15
➤ 49वाँ अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह-2023 का शुभारंभ	16
➤ एआईएसएचई में 22वें से 17वें स्थान पर पहुँचा मध्य प्रदेश	16
➤ मुख्यमंत्री ने खजुराहो में सांस्कृतिक गाँव आदिवर्त का किया लोकार्पण	17
➤ खजुराहो में 'सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी' प्रदर्शनी का उद्घाटन	17
➤ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को करेंगी 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का शुभारंभ	18
➤ मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को मिला केंद्र सरकार से अवॉर्ड	18
➤ प्रदेश की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला प्रमाणीकरण	19
➤ मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023	19
➤ मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का अनुमोदन	20
➤ हलमा की परंपरा	20
➤ जलवायु परिवर्तन और वन-संरक्षण के लिये डब्ल्यू.आर.आई. और एफको में हुआ एमओयू	21

मध्य प्रदेश

भोपाल में पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का हुआ रंगारंग आगाज़

चर्चा में क्यों ?

30 जनवरी, 2023 को पाँचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 का भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में रंगारंग आगाज़ हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की मौजूदगी में इन खेलों का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश की मेजबानी में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में 13 दिन तक 23 आयोजन स्थलों पर छह हज़ार खिलाड़ी 27 खेलों में अपनी प्रतिभा की चमक बिखेरेंगे।
- यह खेल राज्य के आठ शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में आयोजित होंगे। साइकिलिंग का आयोजन नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम वेलड्रोम में होगा।
- भोपाल में एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स (क्याकिंग-कनोइंग और रोइंग), वॉलीबाल और जूडो के मुकाबले होंगे।
- इंदौर में बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, कबड्डी, युवा फुटबॉल (पुरुष) की प्रतियोगिताएँ होंगी।
- ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में 4 अलग-अलग खेल बैंडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक और कलरीपायटू के मुकाबले होंगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में योग और मलखंब के मुकाबले होंगे।
- संस्कारधानी जबलपुर में 4 अलग-अलग खेलों पारंपरिक खेल खो-खो, तीरंदाजी, फेंसिंग और साइकिलिंग (रोड) के मुकाबले होंगे।
- मंडला में मणिपुर और पंजाब के मशहूर पारंपरिक खेल थांगता और गटका के आयोजन होंगे। बालाघाट में महिला युवा फुटबॉल और महेश्वर (खरगोन) में सहस्त्र धारा में सलालम के मुकाबले खेले जाएंगे।
- नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम में साइकिलिंग की प्रतियोगिता होगी।
- गौरतलब है कि भोपाल के तात्या टोपे (TT नगर) स्टेडियम में बनाए गए खेलो इंडिया के मंच पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासतों को दिखाया गया है। मंच को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें महाकालेश्वर उज्जैन, खजुराहो के मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप के साथ ही नर्मदा मैया की बहती हुई सजीव छवि को दिखाया गया है।
- मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को देखते हुए खेलो इंडिया की थीम 'हिन्दुस्तान का दिल धड़का दो' रखी गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी पदक जीतकर आएंगे, उन्हें अगले खेलों की तैयारी के लिये 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पिछले खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 38 मेडल जीते थे।

कटंगी क्षेत्र में रेल संचालन के लिये एम.पी. ट्रांसको ने ऊर्जाकृत किया रेलवे ट्रेक्शन फीडर

चर्चा में क्यों ?

2 फरवरी, 2023 को एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) ने कटंगी क्षेत्र में विद्युत से रेल के सुगम संचालन के लिये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिये एक रेलवे ट्रेक्शन फीडर तैयार किया है और लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित इस फीडर और लाइन का निर्माण, निरीक्षण और परीक्षण कर इसे ऊर्जाकृत कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता दीपक जोशी ने बताया कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बालाघाट-कटंगी रेलखंड पर रेल संचालन के लिये एक 132 के.व्ही. ट्रेक्शन फीडर की मांग की थी। रेलवे द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद एम.पी. ट्रांसको ने इस फीडर और लाइन का निर्माण कर इसे ऊर्जाकृत करने में सफलता प्राप्त की।
- उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 132 के.व्ही. सबस्टेशन कटंगी से रेलवे ट्रेक्शन सबस्टेशन कटंगी तक साढ़े 11 किलोमीटर की इस फीडर को कुल 47 टावर से विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराई गई है।
- इस ट्रेक्शन फीडर के प्रारंभ हो जाने से रेलवे के बालाघाट-कटंगी सेक्शन के लिये अब एक और विद्युत सप्लाई उपलब्ध हो गई है।
- विदित है कि पहले एम.पी. ट्रांसको के 132 के.व्ही. लालबरी सबस्टेशन से 132 के.व्ही. आरटीएस फीडर समनापुर के माध्यम से बालाघाट-कटंगी सेक्शन संचालित होता था।
- इस आरटीएस फीडर के निर्माण से बालाघाट के साथ बालाघाट-कटंगी-तिरोड़ी का लगभग 60 किलोमीटर रेल सेक्शन लाभान्वित हो सकेगा। इससे रेलवे को गुणवत्तापूर्ण विद्युत सतत् प्राप्त हो सकेगी।

गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एन.सी.सी.कैडेट्स हुए सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी. दल के लिये भोपाल में आयोजित चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम में दिल्ली में आयोजित 74वें गणतंत्र दिवस शिविर में सम्मिलित मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के कैडेट्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स का विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कृत किया। इनमें प्रथम स्थान प्राप्त कु. खुशी महावर को 50 हजार रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त कु. आयुषी तिवारी को 30 हजार रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त कु. इशिका गुर्जर को 20 हजार रुपए की सम्मान निधि से सम्मानित किया गया।
- इसी क्रम में राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस में सम्मिलित प्रत्येक कैडेट को 5 हजार रुपए तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रत्येक कैडेट को एक हजार रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के एन.सी.सी. मुख्यालय के ग्रुप कमांडर संजोय घोष को चीफ मिनिस्टर बैनर से सम्मानित किया।
- मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ एन.सी.सी. निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल ए.के. महाजन ने बताया कि 1948 में आरंभ एन.सी.सी. वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मध्य प्रदेश में 55 हजार कैडेट्स को सम्मिलित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि दिल्ली की परेड में मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ निदेशालय के दल ने ग्याहरवाँ स्थान प्राप्त किया। कर्तव्य पथ पर निदेशालय के 15, राष्ट्रीय गार्ड ऑफ ऑनर में 5 और पीएम रैली में 2 कैडेट्स ने भाग लिया। घुड़सवारी में निदेशालय के कैडेट्स ने 2 रजत और दो काँस्य पदक जीते।
- चीफ मिनिस्टर बैनर कार्यक्रम में एन.सी.सी. कैडेट्स द्वारा रूद्र शिव तांडव, पुण्य श्लोक माँ अहिल्या बाई होल्कर की जीवन गाथा पर नृत्य नाटिका, बाँसुरी वादन तथा बधाई नृत्य प्रस्तुत किया गया।

खेलो इंडिया बाक्सिंग में मेजबान मध्य प्रदेश ने जीते 13 पदक

चर्चा में क्यों ?

4 फरवरी, 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मेजबान मध्य प्रदेश ने बाक्सिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीता और कुल 13 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मेजबान मध्य प्रदेश ने बाक्सिंग में 2 स्वर्ण, 4 रजत एवं 7 काँस्य सहित कुल 13 पदक जीते। मध्य प्रदेश के लिये योगेश्वर दत्त एवं मलिका मोर ने स्वर्ण पदक जीते। वहीं हरियाणा 8 स्वर्ण, 5 रजत एवं 2 काँस्य सहित कुल 15 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बना।
- भोपाल के तात्या टोपे नगर स्टेडियम में बाक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले खेले गए। बालक वर्ग के 60-63.5 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में मध्य प्रदेश के योगेश्वर दत्त ने मणिपुर के सी. मोइरैमगधम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अरूणाचल प्रदेश के पक्वा ताव एवं उत्तराखंड के भुवनेश्वर ने काँस्य पदक जीते।
- बालिका वर्ग में मलिका मोर ने मध्य प्रदेश को एक स्वर्ण दिलाया। मलिका मोर ने 45-48 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की भावना शर्मा को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता। उत्तराखंड की आँचल शुक्ला व दिल्ली की संजना ने काँस्य पदक जीता।
- बालक वर्ग में आयुष यादव को 71-75 किग्रा. भार वर्ग में हरियाणा के दीपक के हाथों हार का सामना करना पड़ा। पंजाब के तेजस्वी व मणीपुर के राहुल सिंह ने काँस्य पदक जीते।
- 51-54 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में मध्य प्रदेश के रुद्रजीत सिंह को हरियाणा के अशीष के हाथों हार का सामना करना पड़ा और रजत पदक से संतोष करना पड़ा। 50-52 किग्रा. भार वर्ग के फाइनल में मध्य प्रदेश की कैफी को महाराष्ट्र की देविका घोरपड़े ने हराकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के लिये बालिका वर्ग में विनती ने 70-75 किग्रा. भार वर्ग में रजत पदक जीता, उन्हें फाइनल में हरियाणा की मुस्कान ने हराया।
- बालक वर्ग में अभिषेक तोमर ने 63.5-67 किग्रा. भार वर्ग में, प्रशांत खटाना ने 67-71 किग्रा. भार वर्ग में तथा ऋषभ सिकरवार ने 75-80 किग्रा. भार वर्ग में काँस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में खुशी सिंह ने 60-63 किग्रा. भार वर्ग में, भूमि सिंह ने 54-57 किग्रा. भार वर्ग में एवं राधिका जाटव ने 48-50 किग्रा. भार वर्ग में काँस्य पदक जीता।

कैनोए स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने दो स्वर्ण पदक जीते

चर्चा में क्यों ?

6 फरवरी, 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश के महेश्वर के सहस्रधारा में जारी कैनोए स्लालोम प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने दो स्वर्ण पदक जीते हैं।

प्रमुख बिंदु

- पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कैनोए या वाटर स्लालोम इवेंट के लड़कों के के2 इवेंट में प्रद्युम्न सिंह राठौर ने बाजी मारी। एमेराल्ड इंटरनेशनल स्कूल के छात्र ने 300 मीटर कोर्स पूरा करने के लिये 850 सेकेंड समय लिया और स्वर्ण पदक जीता, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मेघालय के प्रिंसगेन कुरबाह ने 98.310 सेकेंड समय लिया। गुजरात के अनक चौहान को तीसरा स्थान मिला। अनक ने 104.030 सेकेंड में रेस पूरी की।
- इसी तरह लड़कियों के कैनोए स्लालोम सी2 इवेंट में मध्य प्रदेश की मानसी बाथम ने बाजी मारी। मानसी से 250 मीटर कोर्स पर रेस पूरी करने के लिये 596 सेकेंड समय लिया और स्वर्ण पदक जीता। प्रीति पाल (हरियाणा) उनसे काफी पीछे 491.172 सेकेंड के साथ दूसरे और धृति मारिया (कर्नाटक) 559.120 सेकेंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

मुख्यमंत्री ने एचडीएफसी बैंक की 20 शाखाओं का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

6 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन में एचडीएफसी के एटीएम का फीता काटकर बैंक की 20 शाखाओं का वर्चुअली शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा है कि एचडीएफसी बैंक द्वारा प्रदेश में स्व-रोजगार की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त करने में दिया जा रहा सहयोग सराहनीय है।
- मध्य प्रदेश में एचडीएफसी के मुंबई स्थित हेड ऑफिस तथा प्रदेश की 20 शाखाएँ वर्चुअली जुड़ीं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 लाख 33 हजार करोड़ की जमा राशि, 15 लाख 6 हजार करोड़ के अग्रिम ऋण और 22 लाख 95 हजार करोड़ की बैलेंस शीट के साथ एचडीएफसी भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।
- इस बैंक का साख जमा अनुपात (सी.डी. रेशियो) 118 प्रतिशत है, जो दर्शाता है कि बैंक द्वारा राज्य के विभिन्न सेक्टरों को दिया जा रहा ऋण प्रशंसनीय है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंक जनजातीय बहुल और दूरदराज के जिलों में साख जमा अनुपात को बेहतर करने के लिये विशेष रूप से प्रयास करे।
- एचडीएफसी बैंक की जिन शाखाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया, उनमें भोपाल की श्यामला हिल्स शाखा, जबलपुर की स्नेह नगर तथा सदर शाखा, इंदौर की मनोरमा गंज, भानपुरा, भौरासला और बसंत विहार शाखा, उज्जैन की तराना शाखा सम्मिलित हैं।
- साथ ही सीहोर की बुधनी, राजगढ़ की खिलचीपुर और कुरावर, निवाड़ी की ओरछा, खंडवा की मूंदी, खरगौन की महेश्वर, दमोह की पलांदी चौराहा, अनूपपुर की बिजौरी, मंडला की नैनपुर, रीवा की गोलपार्क, सतना की पन्ना रोड तथा आगर-मालवा की नरखेड़ा शाखा भी शामिल हैं।

सुराज नीति-2023

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई घोषणा अनुसार 'शासकीय भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद उपलब्ध भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये आवास निर्माण के लिये सुराज नीति-2023 का मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि का स्वयं संसाधन के रूप में समुचित उपयोग करते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के लिये सुराज कॉलोनी में आवास निर्माण मय आवश्यक अथो-संरचना कार्यों, सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण किये जाने तथा सुराज कालोनी के निर्माण के लिये उचित वित्तीय संसाधन जुटाने तथा शहरी क्षेत्र के उक्त भू-खंडों का सुसंगत योग्य घनत्व से विकास सुनिश्चित करने के लिये यह नीति तैयार की गई है।
- इस नीति का उद्देश्य बिना शासकीय बजटीय सहायता के पुनर्घनत्विकरण नीति के अनुरूप सुराज कॉलोनी के तहत ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के आवासहीनों को किफायती आवास प्रदान करना और अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि का शहर के विकास के लिये सर्वोत्तम उपयोग करना है।
- इस नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- एक अप्रैल 2020 के बाद अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर आवासहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये आवास निर्माण की योजना।
- अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि का एक टुकड़ा निजी डेवलपर को सौंपा जाएगा, जिसके बदले और शेष भूमि में ईडब्ल्यूएस आवास के लिये सुराज टावर बनेगा।
- निजी डेवलपर को दिये जाने वाले भू-खंड के आरक्षित मूल्य की गणना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग की स्थापित नीति के अनुसार खुली निविदाओं के आधार पर की जाएगी।
- छोटे शहरों में मल्टी स्टोरी के स्थान पर 450 वर्ग फीट तक के आवासीय पट्टे पर कॉलोनी विकसित किये जा सकेंगे।
- परियोजना में सुराज कॉलोनी के लिये समस्त आवश्यक अथो-संरचना जैसे सड़क, जल-प्रदाय, बिजली, बगीचा, सामुदायिक भवन और आवश्यकता होने पर स्कूल एवं डिस्पेंसरी भी बना कर दी जाएगी।

- निर्माण होने के बाद इकाइयों का आवंटन कमजोर आय वर्ग के आवासहीन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता एवं फार्मूले के आधार पर जिला स्तर पर किया जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास तथा शासकीय परियोजनाओं जैसे सड़क इत्यादि में आवश्यकता होने पर पुनर्वास भी किया जा सकता है।
- योजना के क्रियान्वयन के लिये अन्य सभी प्रक्रियाएँ राज्य में स्थापित रिडेंसीफिकेशन नीति 2022 के अनुसार रहेंगी।
- सुराज टावर कॉलोनी निर्माण के बाद अगले 5 सालों तक डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंतर्गत विकास और 3 वर्ष तक कॉलोनी का रख-रखाव संचालन एवं मरम्मत का दायित्व निजी डेवलपर का रहेगा।

मध्य प्रदेश की मंत्रि-परिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

7 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्वर्गीय आर. एस. राठौर, अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी की कोरोना संक्रमण के कारण 19 अप्रैल 2021 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनकी विवाहित पुत्री श्रद्धा मालवी को पात्रता न होते हुए भी मानवीय आधार एवं उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर के निर्णय के अनुक्रम में विशेष प्रकरण मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए।
- इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अनुकंपा संबंधी आदेश 29 सितंबर, 2014 के प्रावधानों में मंत्रि-परिषद द्वारा यह नीतिगत निर्णय भी लिया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के लिये पुत्र एवं पुत्री दोनों को समान अधिकार हैं, चाहे पुत्रियाँ विवाहित ही क्यों न हों। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग नीति में आवश्यक संशोधन करेगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग में वर्ष 2022-23 में 'मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना' में 150 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत पूर्व में मंत्रि-परिषद से स्वीकृत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में समाहित विशेष पिछड़ी जनजातियों हेतु स्वीकृत घटक 'मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम' में संशोधन किये गए हैं। अब इस योजना में मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम में बैगा जनजाति के साथ सहरिया और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी शामिल किया गया है।
- इस कार्यक्रम में दुधारू गाय की इकाई के साथ दुधारू भैंस की इकाई को भी शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में दुधारू गाय के साथ दुधारू भैंस को भी सम्मिलित करने के परिप्रेक्ष्य में योजना का नाम 'मुख्यमंत्री दुधारू गाय प्रदाय कार्यक्रम' के स्थान पर 'विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम' किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने राज्य में गत वर्ष से लागू नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 में स्टोरेज आधारित परियोजनाओं के विकास को मान्य किया। इसी कड़ी में मंत्रि-परिषद द्वारा पंप हाईड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा निविदा प्रक्रिया संपादित करने का निर्णय लिया।
- इस निर्णय से नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा की निरंतरता और अधिक सुनिश्चित होगी तथा ग्रिड स्थायित्व में भी लाभ होगा। राज्य में पंप हाईड्रो परियोजनाओं के विकास के लिये नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना को अनुमोदन प्रदान करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देशिका बनाने/संशोधन/ स्पष्टीकरण दिये जाने के लिये विभाग को अधिकृत किया गया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति की अनुशंसा अनुसार स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार, संचालन एवं नवीन डिजास्टर रिकवरी साइट की नेशनल डाटा सेंटर भुवनेश्वर में स्थापना तथा वर्तमान में स्थापित हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिये कुल परियोजना व्यय 161 करोड़ 95 लाख रुपए का अनुमोदन किया गया।

एआईएफ योजना में मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी, 2023 को एमपी फार्म गेट एप तथा आईएफ अंतर्गत कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित कार्यशाला में मध्य प्रदेश के किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि कृषि अधो-संरचना मद (एआईएफ) के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- एआईएफ योजना में कृषि अधो-संरचना निर्माण के लिये 3 प्रतिशत ब्याज छूट पर बैंक से ऋण लेकर वेयर-हाउस, कस्टम हायरिंग सेंटर, कोल्ड-स्टोरेज, ग्रेडिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट आदि के कार्य किये जा रहे हैं।
- मध्य प्रदेश में एआईएफ योजना में अभी तक 5070 प्रकरण में 3930 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत कर मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। अब तक इसमें 4552 प्रकरण में 3040 करोड़ रुपए की राशि वितरित की जा चुकी है, जो कि दूसरे राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022: मध्य प्रदेश ने तीन स्वर्ण और एक रजत जीता

चर्चा में क्यों ?

8 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के उज्जैन के माधव सेवा न्यास में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2022 में मलखंभ मुकाबलों में मेजबान मध्य प्रदेश ने दो स्वर्ण और एक रजत पदक तथा भारोत्तोलन में एक स्वर्ण अपने नाम किये।

प्रमुख बिंदु

- लड़कों के व्यक्तिगत आलराउंड इवेंट में प्रणव ने 26.50 अंक के साथ स्वर्ण जीता जबकि मध्य प्रदेश की टीम ने रैंकिंग (लड़के एवं लड़कियाँ संयुक्त) का स्वर्ण 207.20 अंकों के साथ जीता। लड़कियों के व्यक्तिगत आलराउंड इवेंट में मध्य प्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने रजत जीता।
- मलखंभ में लड़कों के व्यक्तिगत आलराउंड इवेंट में शार्दूल (महाराष्ट्र) 26.10 अंकों के साथ दूसरे और राकेश वेरडा (छत्तीसगढ़) 25.90 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे। टीम रैंकिंग का रजत महाराष्ट्र (205.60) को और कांस्य छत्तीसगढ़ (201.25) को मिला।
- सिद्धि ने लड़कियों के इवेंट में 17.30 अंकों के साथ दूसरा स्थान पाया। इस स्पर्धा का स्वर्ण महाराष्ट्र की समीक्षा सुराड़कर ने जीता। कांस्य पदक महाराष्ट्र की ही तनुश्री जाधव को मिला।
- इसी तरह मध्य प्रदेश के वेलुरू अजय बाबू ने भारोत्तोलन में 81 किग्रा वर्ग में स्वर्ण जीता। वेलुरू ने स्लैच-135 किग्रा, क्लीन एंड जर्क-162 किग्रा, कुल- 297 किग्रा के साथ पहला स्थान हासिल किया।

मध्य प्रदेश ने रोइंग में जीते दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य पदक

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश के खिलाडियों ने रोइंग में दो स्वर्ण, दो रजत और तीन कांस्य सहित कुल सात पदक जीते।

प्रमुख बिंदु

- राजधानी भोपाल के बड़े तालाब पर रोइंग में बालिका वर्ग के सिंगल स्कल में मध्य प्रदेश की मोनिका भदौरिया ने स्वर्ण पदक जीता।
- रोइंग की बालिका डबल स्कल में मध्य प्रदेश की संतोष यादव और जिज्ञासा रेगर की जोड़ी ने रजत पदक प्राप्त किया।
- रोइंग के बालक वर्ग के सिंगल स्कल में मध्य प्रदेश के प्रभाकर राजावत ने रजत पदक जीता।
- रोइंग के डबल स्कल में मध्य प्रदेश के अंकित सेधव और हरिओम ठाकुर की जोड़ी ने रजत पदक जीता।
- रोइंग के कॉक्लेस पेयर में मध्य प्रदेश के गोपाल ठाकुर और योगेश ठाकुर की जोड़ी ने रजत पदक जीता।
- रोइंग के कॉक्लेस फोर में मध्य प्रदेश के छोटूनाथ, बंटी सेधव, वेदांश और धीरज वर्मा ने कांस्य पदक जीता।

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की SATTE 2023 में भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

9 फरवरी, 2023 को केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी यात्रा और पर्यटन प्रदर्शनी- साउथ एशिया ट्रेवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज SATTE 2023 के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड भागीदारी कर रहा है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा SATTE 2023 के माध्यम से यात्रा और पर्यटन उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों को प्रदेश के पर्यटन स्थल, स्थापत्य कला, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य से अवगत कराया जा रहा है।
- हितधारकों को राज्य की परिवहन सुगमता, सुरक्षित वातावरण और नागरिकों के आतिथ्यभाव के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम स्थल में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का स्टॉल क्रमांक 1-60 हॉल क्रमांक 9 में लगाया गया है।
- स्टॉल पर आगंतुकों को ऑनलाइन सहायता से वर्चुअल रियलिटी तकनीक से साँची, अमरकंटक, नर्मदा घाट और अन्य गंतव्यों का आभासी पर्यटन कराया जा रहा है।
- SATTE 2023 में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का भागीदारी करने का उद्देश्य अपने विभिन्न हितधारकों से मिलना और 'हिंदुस्तान के दिल' मध्य प्रदेश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के अवसर सृजित करना है।
- उल्लेखनीय है कि इस प्रदर्शनी का आयोजन 9 से 11 फरवरी तक किया जाएगा।

मध्य प्रदेश ने हॉकी में जीता स्वर्ण और रजत पदक

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी टीम ने फाइनल मुकाबले में हॉकी का पावरहाउस कहे जाने वाले ओडिशा को 3-2 से मात देकर गोल्ड मेडल जबकि महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने झारखंड की टीम को फाइनल में कड़ी टक्कर दी। प्रदेश की लड़कियाँ बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक-एक से बराबरी करने में सफल हो गई थी, लेकिन पेनाल्टी शूटआउट में वे 4 के मुकाबले 3 गोल ही कर सकीं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
- पुरुष एवं महिला हॉकी प्रतियोगिताओं का फाइनल एमपी हॉकी अकादमी, ग्वालियर में खेला गया।
- पुरुष वर्ग में पंजाब ने झारखंड को 2-0 से हरा कर कांस्य पदक जीता, वहीं महिला वर्ग में हरियाणा ने ओडिशा को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीता।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2022 में पदक तालिका में मध्य प्रदेश तीसरे क्रम पर है।

राष्ट्रीय मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति के आधार पर जिलों एवं विकासखंड की रैंकिंग तय

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को राष्ट्रीय मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश के जिलों और विकासखंडों की रैंकिंग निर्धारित की है।

प्रमुख बिंदु

- इस परीक्षा के आधार पर घोषित रैंकिंग में दमोह जिला प्रथम स्थान पर रहा जबकि निवाड़ी जिला सबसे निचले पायदान पर रहा है।
- जिलों के साथ ही विकासखंडों के प्रदर्शन को भी राज्य स्तर से परखा गया है। जिसके अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रीवा जिला मुख्यालय का 'रीवा' विकासखंड प्रथम स्थान पर और डिंडौरी जिले का 'बजाग' विकासखंड अंतिम स्थान पर है।

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा में शासकीय विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं और इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को उनकी आगे की पढ़ाई के लिये कक्षा 9 से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12 हजार रुपए छात्रवृत्ति प्राप्त होती है।
- सत्र 2022-23 की यह परीक्षा 6 नवंबर 2022 को संपन्न हुई थी, जिसमें इस बार मध्य प्रदेश के रिकार्ड 2 लाख 52 विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता की गई थी।
- इस परीक्षा के परिणाम का राज्य शिक्षा केंद्र ने विस्तृत विश्लेषण कर जिलों और विकासखंडों की रैंकिंग निर्धारित की है, जिसमें 4 मुख्य मापदंड के आधार पर जिलों के आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है।
- कुल नामांकित विद्यार्थियों के अनुपात में परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षाफल का औसत स्कोर, परीक्षा फल का उत्कृष्ट स्कोर और राज्य की मेरिट सूची में प्रथम 100 में आए विद्यार्थियों की संख्या को मापदंड के रूप में रखा गया था।
- यह विश्लेषण गुणवत्ता शिक्षा के प्रयासों की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र शिक्षा की गुणवत्ता का मैदानी स्तर पता कर सकते हैं और जहाँ कुछ कमी है वहाँ आवश्यक सुधारात्मक पहल की जा सकती है।

इंदौर का ग्रीन ब्रांड बना नंबर-1

चर्चा में क्यों ?

10 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम द्वारा ग्रीन ब्रांड जारी किया गया जिसे आमजन और निवेशकों ने कुछ घंटे में ही खरीदकर नंबर-वन बना दिया है।

प्रमुख बिंदु

- इस उपलब्धि के पीछे इंदौर की साख प्रमुख आधार है। प्रदेश के किसी नगरीय निकाय ने देश के प्रथम ग्रीन पब्लिक ब्रांड के माध्यम से इस क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त की है।
- गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम द्वारा सौर ऊर्जा क्षेत्र में संयंत्र स्थापना के लिये जारी ग्रीन ब्रांड इश्यू के माध्यम से सिर्फ दो घंटे की अवधि में 300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सामने आए। बाजार बंद होने तक यह राशि करीब 650 करोड़ रुपए हो गई।
- ओवर सब्सक्राइब की इस स्थिति को आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने विशेष उपलब्धि माना है।
- उल्लेखनीय है कि इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में देश में निरंतर 6 बार प्रथम आने के साथ ही अब ग्रीन ब्रांड के माध्यम से नई उपलब्धि अर्जित करते हुए एक ब्रांड बन चुका है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स- 2022 में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

11 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का समापन हुआ जिसमें मध्य प्रदेश ने 39 स्वर्ण पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स - 2022 में 56 स्वर्ण, 55 रजत एवं 50 काँस्य पदक सहित कुल 161 पदक प्राप्त कर ओवर ऑल महाराष्ट्र चैंपियन रहा। वहीं 41 स्वर्ण, 32 रजत एवं 55 काँस्य सहित कुल 128 पदक प्राप्त कर हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा है।
- मध्य प्रदेश 39 स्वर्ण, 30 रजत एवं 27 काँस्य पदक सहित कुल 96 पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर रहा।
- मध्य प्रदेश ने कयाकिंग एवं कैनोइंग में 11 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक, एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण सहित कुल 14 पदक एवं मलखंब में 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक प्राप्त कर बेहतर प्रदर्शन किया।
- उल्लेखनीय है कि पिछले खेलो इंडिया गेम्स में मध्य प्रदेश देश में 8वें स्थान पर था। इस बार प्रदेश ने इन खेलों में प्रगति की है।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स -2022 के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के भोपाल के बोट क्लब पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने खेलो इंडिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक पृथक् कार्यक्रम में पुरस्कृत और सम्मानित करने की घोषणा की।

- गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से 11 फरवरी, 2023 तक किया गया। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) का पाँचवाँ संस्करण था, इनका पहली बार आयोजन 2018 में राजधानी नई दिल्ली में किया गया था।
- यह संस्करण मध्य प्रदेश के आठ शहरों में आयोजित किया गया, जिसमें राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट शहर शामिल हैं। इसके आलावा दिल्ली में भी कुछ खेलों का आयोजन हुआ।
- विदित है कि मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का पाँचवाँ राज्य है। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में प्रथम संस्करण के बाद, महाराष्ट्र ने 2019 में इस आयोजन की मेजबानी की थी, जबकि असम ने साल 2020 में और पिछला संस्करण वर्ष 2021 में हरियाणा में आयोजित किया गया था।
- खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इस संस्करण में 27 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स को खेलों के इतिहास में पहली बार शामिल किया गया। कैनो स्लैलम, कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे नए खेल भी इस स्वदेशी खेलों में शामिल हुए।
- भारत के 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 5,000 से अधिक एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हिस्सा लिया। जहाँ एथलीटों ने 27 खेलों में 973 पदक - 295 स्वर्ण, 295 रजत और 383 काँस्य के लिये अपनी चुनौती पेश की।
- इस वर्ष मेजबान राज्य मध्य प्रदेश ने इन खेलों में सबसे बड़ी टीम (474 एथलीट) उतारी थी।

अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने 66वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2022-23 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में आतंकवाद, नक्सलवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के खिलाफ कार्यवाही के तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा किये जाने से इन समस्याओं पर प्रभावी कार्यवाही करने में पुलिस को मदद मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में कुल अपराधों में 19 प्रतिशत की कमी आई है।
- इस पुलिस मीट के दौरान एंटी सैबोटेज चेक, सांइटिफिक इन्वेस्टिगेशन, पुलिस फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, कंप्यूटर अवेयरनेस एवं डॉग स्क्वॉड आदि विषयों पर परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विषयों के बारे में पुलिसकर्मियों के ज्ञान में वृद्धि होगी।
- मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश में इसके पहले 2 बार पुलिस ड्यूटी मीट हो चुकी है। मीट में विभिन्न प्रदेशों की पुलिस की कॉमन प्रबलम्स पर चर्चा होती है। एक-दूसरे के अच्छे कार्यों को शेयर करते हैं। पुलिस ड्यूटी मीट में जितनी भी प्रतियोगिताएँ होंगी सभी का संबंध प्रतिदिन के कार्यों से है।
- इस पुलिस ड्यूटी मीट में विभिन्न प्रदेशों के 24 दल शामिल हुए हैं।
- पुलिस ड्यूटी मीट में आंध्र प्रदेश, बिहार, बीएसएफ, छत्तीसगढ़, सीआरपीएफ, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आईटीबीपी, जम्मू-काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, रेलवे सुरक्षा बल, एसएसबी, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के दल शामिल हुए हैं।

इंदौर में सुपर कॉरिडोर पर यश टेक्नोलॉजी के आईटी कैंपस का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के सुपर कॉरिडोर में यश टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए गए अत्याधुनिक और सबसे बड़े कैंपस का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 5 एकड़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कैंपस में 2,500 लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में इसका विस्तार 15 एकड़ में होगा तथा इससे 12 हजार 500 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इसमें इंदौर और मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतीकरूप 5 युवाओं को ऑफर लेटर दिये।
- यश टेक्नोलॉजी के सीईओ मनोज बाहेती ने बताया कि वे मध्य प्रदेश के बैतूल के पास स्थित एक छोटी सी जगह बैतूल बाजार के रहने वाले हैं। इंदौर के जीएसआईटीएस से इंजीनियरिंग करने के बाद वर्ष 1996 में अमेरिका में यश टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी।

राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिये प्रदेश में ललित कलाओं के क्षेत्र में राज्य रूपंकर कला पुरस्कार घोषित कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 20 फरवरी, 2023 को खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर राज्य रूपंकर कला पुरस्कार में 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
- पुरस्कार के लिये घोषित कलाकारों को 51 हजार रुपए की सम्मान राशि और प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पुरस्कृत और चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी 20 से 26 फरवरी, 2023 तक खजुराहो नृत्य समारोह स्थल में लगेगी।
- राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार जबलपुर के अमित कुमार सिन्हा को उनकी कलाकृति 'द शाइनिंग मेकर' के लिये दिया जाएगा तथा मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार भोपाल की समीक्षा राठौर को 'शीर्षक विहिन' के लिये प्रदान किया जाएगा।
- वहीं राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये सैयद हैदर रजा पुरस्कार भोपाल के पॉपिल मन्ना को 'डेप्य ऑफ फेयरनेसन' के लिये, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार धार के प्रेम कुमार सिंह को 'अनटाईटल-1' के लिये, जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार भोपाल के मान सिंह व्याम को 'जिंदगी एक सफर के लिये', विष्णु चिंचालकर पुरस्कार इंदौर के उपेंद्र उपाध्याय को 'सेमल की बहार' के लिये, नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार ग्वालियर के ओमप्रकाश माहौर को 'रंगों का बचपन' के लिये, रघुनाथ कृष्णराव फड़के पुरस्कार भोपाल के गिरीश बा. उरकुड़े को 'अनटाईटल-2' के लिये, राममनोहर सिन्हा पुरस्कार भोपाल की शिवानी दुबे को 'हिस्टोरिसिटी-6' के लिये और लक्ष्मीशंकर राजपूत पुरस्कार जबलपुर की अंजलि राउत को 'प्रिंटेड क्वीन-1' के लिये प्रदान किया जाएगा।

जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा इस्लामनगर

चर्चा में क्यों ?

14 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के जगदीशपुर (इस्लामनगर) के चमन महल में गौरव दिवस कार्यक्रम के अवसर पर जगदीशपुर के नामकरण शिला का अनावरण किया। इस्लामनगर अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा 1 फरवरी, 2023 को राजपत्र पर अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें नाम में बदलाव की सूचना दी गई है। इस अधिसूचना में लिखा गया है कि गृह मंत्रालय के पत्र का संसूचित अनापत्ति के अनुसरण के बाद भोपाल जिले के इस्लाम नगर गाँव का नाम परिवर्तित किया जा रहा है। यह अधिसूचना मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम के से जारी की गई है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 26 करोड़ 71 लाख 86 हजार रुपए के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।
- उल्लेखनीय है कि जगदीशपुर भोपाल जिले में स्थित एक ग्राम पंचायत है। यह तहसील हुजूर में फंदा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। पूर्व में जगदीशपुर (इस्लामनगर) भोपाल रियासत की राजधानी हुआ करती थी। जगदीशपुर देवड़ा राजपूतों का गढ़ था। जगदीशपुर को राजपूत शासकों ने बसाया था। वर्ष 1715 से पहले यहाँ के शासक नरसिंह देवड़ा चौहान थे।

- 308 साल पहले औरंगजेब की मौत के बाद उसकी सेना का एक सैनिक दोस्त मोहम्मद खान भागकर उत्तर प्रदेश, मालवा और मंगलगढ़ होते हुए जगदीशपुर पहुँच गया। पहले उसने जगदीशपुर पर हमला किया, जिसमें उसे करारी शिकस्त मिली। उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान ने राजा नरसिंह देवड़ा को भोजन का निमंत्रण दिया था और भोजन करते समय उसकी हत्या कर दी। फिर दोस्त मोहम्मद खान ने जगदीशपुर पर अधिकार कर इसका नाम इस्लामनगर रख दिया था।
- जगदीशपुर का किला अपनी वास्तु-कला के लिये जाना जाता है। पर्यटन स्थल जगदीशपुर में गोंड महल, रानी महल एवं चमन महल प्रमुख हैं।

मुख्यमंत्री ने कूनो में 12 और चीतों को छोड़ा

चर्चा में क्यों ?

18 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले में स्थित कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को बाड़े में छोड़ा। इनमें 7 नर चीते और 5 मादा चीते शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- दक्षिण अफ्रीका से लाए गए इन 12 चीतों को मिलाकर अब कूनो में 20 चीते हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म-दिन 17 सितंबर, 2022 को नामीबिया से लाए 8 चीतों को कूनो में छोड़ा था।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश का पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान वन्य-जीव प्रेमियों के लिये सबसे अनूठा गंतव्य है। कूनो में करधई, खैर और सलाई की बहुतायत वाले लुभावने जंगल हैं और विशाल घास के मैदानों में दर्जनों की संख्या में घास चरते हुए वन्यजीव हैं।
- यह क्षेत्र लगभग 350 वर्ग किमी. के अभयारण्य के रूप में शुरू हुआ था और एक पत्ती के आकार का था जिसके बीचों - बीच में एक रीढ़ की हड्डी की तरह कुनो नदी बहती है। यह नदी न केवल जंगल में एक निरंतर पानी की आपूर्ति रखने और जंगल की सिंचाई करने में मदद करती है, बल्कि इससे इस संरक्षित क्षेत्र का नाम भी पड़ा है।
- कूनो नेशनल पार्क/कूनो वन्य-जीव डिवीजन और आसपास का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से वन्य-जीवों से समृद्ध रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में भी घने जंगल के रूप में जाना जाता था। कूनो नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से जैव विविधता से समृद्ध रहा है।
- राज्य सरकार ने इस स्थान को महत्त्व को महसूस करते हुए वर्ष 1981 में लगभग 3300 वर्ग किमी. के बड़े वन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 345 वर्ग किमी. के कूनो वन्य-जीव अभयारण्य की स्थापना की। वन्य-जीव संरक्षण को और मजबूत करने और इस क्षेत्र के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त 891 वर्ग किमी. क्षेत्र को बफर के रूप में जोड़कर वर्ष 2002 में 1235 वर्ग किमी. के कूनो वन्य-जीव प्रभाग की स्थापना की गई।
- क्षेत्र में शुष्क घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय नदी वाले वन शामिल हैं। यह पशुओं की विभिन्न प्रजातियों में समान रूप से समृद्ध है। यह क्षेत्र वन्य-जीव के लिये विभिन्न अनुकूल कारकों का एक दुर्लभ रहवास स्थल है। इस क्षेत्र को चीतों के के पुनर्वास लिये सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना गया।
- कूनो नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में मुख्य रूप से करधई, सलाई, खैर के पेड़ों का वर्चस्व है, जो ज्यादातर मिश्रित जंगलों के बीच हैं। इससे वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ होने में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर, 123 प्रजातियों के पेड़, झाड़ियों की 71 प्रजातियाँ, बेलों और विदेशी वनस्पति की 32 प्रजातियाँ, बाँस और घास की 34 प्रजातियाँ कूनो नेशनल पार्क में पाई जाती हैं।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में शराब को हतोत्साहित करने के निर्णय के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में शराब को हतोत्साहित करने के लिये कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं।
- प्रदेश में शराब के सभी अहाते और शॉप बार बंद किये जाएंगे।
- मदिरा दुकानों में बैठकर मदिरा पीने की अनुमति नहीं होगी।
- शराब की दुकान के लिये शैक्षणिक और धार्मिक संस्थानों के आसपास के 50 मीटर के दायरे को बढ़ाकर 100 मीटर किया जाएगा।
- शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने एवं सजा के प्रावधान कड़े किये जाएंगे।
- मंत्रि-परिषद ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 परिशिष्ट-1 में संशोधन करते हुए राहत राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।
- निर्णय अनुसार शरीर के किसी अंग अथवा आँख/आँखों की हानि के लिये 40% और 60% तक अपंगता होने पर 59 हजार 100 रुपए के स्थान पर 74 हजार रुपए प्रति व्यक्ति तथा 60% से अधिक अपंगता होने पर 2 लाख रुपए के स्थान पर 2 लाख 50 हजार रुपए दिया जाएगा।
- इसी तरह गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को एक सप्ताह से अधिक दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने पर 12 हजार 700 रुपए के स्थान पर 16 हजार रुपए प्रति व्यक्ति तथा एक सप्ताह से कम अवधि के लिये अस्पताल में भर्ती होने पर 4 हजार 300 रुपए के स्थान पर 5 हजार 400 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा।
- बाढ़ की स्थिति में भूमि और अन्य नुकसान के लिये सहायता-
- कृषि योग्य भूमि वाले खेतों में रेत या पत्थर (3 इंच से अधिक) आ जाने पर पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर मलबा हटाने के लिये, फिश फार्म में डिसेलिटिंग या पुनस्थापन अथवा मरम्मत सफाई के लिये राहत 12 हजार 200 रुपए के स्थान पर 18 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
- इसी तरह भूस्खलन, हिमस्खलन, नदियों के रास्ता बदलने के कारण सीमांत या लघु कृषक के भूमि स्वामित्व की भूमि के नष्ट होने पर राहत 37 हजार 500 रुपए के स्थान पर 47 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
- पशु-पक्षी (मुर्गा/मुर्गी) हानि के लिये आर्थिक सहायता-
- दुधारू पशु गाय/भैंस/ऊँट आदि के लिये राहत राशि 30 हजार प्रति पशु के स्थान पर 37 हजार 500 रुपए एवं भेड़ बकरी/ सूअर के लिये राहत 3 हजार रुपए के स्थान पर 4 हजार रुपए दिया जाएगा।
- गैर-दुधारू पशु ऊँट/घोड़ा/बैल/भैंसा आदि के लिये राहत राशि 25 हजार रुपए प्रति पशु के स्थान पर 32 हजार रुपए प्रति पशु किया जाएगा एवं बछड़ा (गाय, भैंस)/ गधा /पोनी/ खच्चर हेतु राहत 16 हजार रुपए प्रति पशु के स्थान पर 20 हजार रुपए दिया जाएगा।
- अस्थायी पशु शिविर में रखे गए बड़े पशुओं के लिये 70 रुपए पशु प्रति दिवस के स्थान पर 80 रुपए एवं छोटे पशुओं के 35 रुपए प्रति पशु प्रति दिवस के स्थान पर 45 रुपए दिया जाएगा।
- इसी तरह पक्षी (मुर्गा/ मुर्गी) हानि के लिये 60 रुपए (10 सप्ताह से अधिक आयु के) प्रति पक्षी के स्थान पर 100 रुपए प्रति पक्षी दिया जाएगा।
- बाढ़ एवं तूफान से प्रभावित मछुआरों को दी जाने वाली सहायता-
- नाव की आंशिक क्षति होने पर मरम्मत के लिये 4 हजार 100 रुपए के स्थान पर 6 हजार रुपए दिया जाएगा।
- जाल या अन्य उपकरणों की मरम्मत के लिये 2 हजार 100 रुपए के स्थान पर 3 हजार रुपए दिया जाएगा।
- नाव नष्ट होने पर 12 हजार रुपए के स्थान पर 15 हजार रुपए दिया जाएगा।
- इसी तरह नैसर्गिक आपदा यथा सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि से मछली पालने वालों को मछली बीज नष्ट होने पर प्रभावित को 8 हजार 200 रुपए के स्थान पर 10 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा।
- बुनकरो/हस्तशिल्पियों को दी जाने वाली सहायता-
- नैसर्गिक आपदा से प्रभावित बुनकर/परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में काम करने वाले हस्त शिल्पी को उनके उपकरण/औजार और उनके द्वारा तैयार माल अथवा कच्चे माल के क्षतिग्रस्त होने पर कच्चे माल या धागा और अन्य तत्संबंधी रंग, रसायन आदि क्रय करने पर प्रति बुनकर/ शिल्पी हेतु राहत राशि अधिकतम 4 हजार 100 रुपए के स्थान पर 5 हजार रुपए प्रति शिल्पकार दिया जाएगा।

नष्ट हुए मकानों के लिये आर्थिक अनुदान सहायता-

- पूर्ण नष्ट (मरम्मत योग्य नहीं) और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त (जहाँ क्षति 50 प्रतिशत से अधिक हो) पक्के/कच्चे मकान के लिये वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर राहत राशि अधिकतम 95 हजार 100 रुपए के स्थान पर मैदानी इलाकों में 1 लाख 20 हजार एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1 लाख 30 हजार रुपए दी जाएगी।
- झुग्गी झोपड़ी (झुग्गी/झोपड़ी से तात्पर्य है कच्चे घर से निम्नतर फूस मिट्टी प्लास्टिक सीट आदि से निर्मित घर) पूर्ण नष्ट होने पर राहत राशि 6 हजार के स्थान पर 8 हजार रुपए दी जाएगी।
- इसी तरह आंशिक क्षतिग्रस्त (जहाँ क्षति 15 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो) पक्के मकान के लिये राहत राशि 5 हजार 200 के स्थान पर 6 हजार 500 रुपए एवं कच्चे मकान के लिये 3 हजार 200 के स्थान पर 4 हजार रुपए दी जाएगी। साथ ही मकान से संलग्न पशु घर के लिये राहत राशि 2 हजार 100 के स्थान पर 3 हजार रुपए प्रति पशु घर दी जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की कतिपय धाराओं में संशोधन किये जाने के लिये म.प्र. नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। यह विधेयक विभाग के अंतर्गत प्रशासित अधिनियमों के कतिपय प्रावधानों को डिफ्रिमांलाइज करने के संबंध में लाया जा रहा है।
- मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदाय किया जाना) संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इससे शहरों में गरीबों की आवास की समस्या के निराकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों को प्रदाय किया जाना) अधिनियम 1984 के अंतर्गत गरीबों को आवासीय भूमि के पट्टे देने की पात्रता तिथि में वृद्धि करके कटऑफ तिथि 31 दिसंबर, 2014 से 31 दिसंबर, 2020 की जा रही है।
- मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीण के सृजन को मंजूरी दी है।

मध्य प्रदेश का सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिये उत्कृष्ट राज्य के रूप में चयन

चर्चा में क्यों ?

19 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिये उत्कृष्ट राज्य के रूप में चुना गया है।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्रीय सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो द्वारा मध्य प्रदेश को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान किया गया है।
- मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में विगत 15 वर्षों में सिंचाई क्षमता को 7 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया गया है।
- विगत 3 वर्षों में मध्य प्रदेश पाईप प्रणाली के माध्यम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डेवेलपमेंट कोर ग्रुप का गठन

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को राज्य शासन ने प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्यों, केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा तथा जनोन्मुखी विकास के लिये आवश्यक योजनाओं/कार्यक्रमों की स्वीकृति की अनुशांसा किये जाने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में डेवेलपमेंट कोर ग्रुप का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस डेवेलपमेंट कोर ग्रुप की बैठक वर्ष में दो बार होगी।
- समिति में पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वन, जल संसाधन, ऊर्जा, गृह, वित्त, लोक निर्माण, आदिम जाति कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य एवं महिला बाल विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एएनओ, सदस्य होंगे।
- अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कोर ग्रुप के सदस्य सचिव होंगे।

49वाँ अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह-2023 का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

20 फरवरी, 2023 को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में खजुराहो के सांसद तथा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने सात दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य समारोह-2023 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 49वाँ खजुराहो नृत्य महोत्सव पश्चिमी मंदिर समूह परिसर के अंदर चंदेलकालीन कंदारिया महादेव मंदिर तथा देवी जगदंबा मंदिर के मध्य विशाल मुक्ताकाशी मंच पर 26 फरवरी तक चलेगा।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग द्वारा उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद्, भोपाल के माध्यम से विश्व धरोहर पर्यटन नगरी खजुराहो में प्रतिवर्ष खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है।
- भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों पर केंद्रित यह देश का शीर्षस्थ समारोह है जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त है। इस समारोह में देश एवं विश्व के विख्यात कलाकार अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ देते हैं।
- खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी और तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर किया जाता रहा है। तब से लेकर आज तक यह नृत्य समारोह खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण में आयोजित होता आ रहा है।
- खजुराहो नृत्य समारोह में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडीसी, कथक, मोहिनीअटेम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं।
- समारोह के माध्यम से नृत्य में शास्त्रीयता की गरिमा बनाए रखने के साथ नवाचार करने का प्रयास किया जाता रहा है।
- समारोह के शुभारंभ पर सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने 10 कलाकारों को मध्य प्रदेश राज्य रूपंकर कला पुरस्कार 2023 भी प्रदान किये।
 - ◆ राज्य रूपंकर कला पुरस्कारों में वर्ष 2022-23 के लिये देवकृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार जबलपुर के अमित कुमार सिन्हा को कलाकृति 'द शाइनिंग मेकर' के लिये,
 - ◆ मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार भोपाल की सुश्री समीक्षा राठौर को 'शीर्षक विहीन' के लिये,
 - ◆ सैयद हैदर रजा पुरस्कार भोपाल के पाँपिल मन्ना को 'डेपथ ऑफ फेयरनेशन' के लिये,
 - ◆ दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार धार के प्रेम कुमार सिंह को 'अनटाइटल 1' के लिये,
 - ◆ जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार भोपाल के मान सिंह व्याम को 'जिंदगी एक सफर' के लिये,
 - ◆ विष्णु चिंचालकर पुरस्कार इंदौर के उपेंद्र उपाध्याय को 'सेमल की बहार' के लिये,
 - ◆ नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार ग्वालियर के ओमप्रकाश माहौर को 'रंगों का बचपन' के लिये,
 - ◆ रघुनाथ कृष्णराव फडके पुरस्कार भोपाल के गिरीश बा. उरकुड़े को 'अनटाइटल 2' के लिये,
 - ◆ राममनोहर सिन्हा पुरस्कार भोपाल की सुश्री शिवानी दुबे को 'हिस्टोरीसिटी 6' के लिये
 - ◆ लक्ष्मीशंकर राजपूत पुरस्कार जबलपुर की सुश्री अंजलि राऊत को 'प्रिंटेड क्वीन 1' के लिये प्रदान किया गया।
- इन कलाकारों को 51 हजार रुपए की सम्मान निधि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए। सभी कलाकारों की पुरस्कृत कृतियाँ राज्य रूपंकर कला पुरस्कार प्रदर्शनी में लगेगी।

एआईएसएचई में 22वें से 17वें स्थान पर पहुँचा मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

21 फरवरी, 2022 को एआईएसएचई शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार में उप महानिदेशक आर. राजेश ने उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी में एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि एआईएसएचई के माध्यम से उच्च शिक्षा संस्थानों के डाटा प्रविष्टि के कार्य में मध्य प्रदेश 22वें स्थान से 17वें स्थान पर आ गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में लगभग साढ़े चार लाख नए विद्यार्थियों का डाटा, पोर्टल में दर्ज हुआ है।
- आर. राजेश ने कहा कि एआईएसएचई द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि पोर्टल पर दर्ज किया जाने वाले आँकड़े पूरी तरह सटीक हों, क्योंकि इस डाटा बेस का इस्तेमाल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नीति निर्माण, बजट आवंटन एवं अनुसंधान में किया जाता है। इस डाटा बेस का इस्तेमाल कई बार यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ जैसे विश्वस्तरीय संगठन भी करते हैं।
- निजी विश्वविश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. भरत शरण ने कहा कि वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्राओं के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- उल्लेखनीय है कि एआईएसएचई उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण संस्थान है, जो वर्ष 2010-11 से प्रारंभ हुआ है। इसके माध्यम से सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विद्यार्थी शिक्षक से संबंधित संपूर्ण जानकारी, परीक्षा परिणाम, पाठ्यक्रम, शिक्षा की गुणवत्ता के लिये संस्थाओं में होने वाले प्रशिक्षण एवं कार्यक्रम, बुनियादी सुविधाएँ, आर्थिक संसाधन के आँकड़े एक पोर्टल के माध्यम से एकत्रित किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने खजुराहो में सांस्कृतिक गाँव आदिवर्त का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में जी-20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक के आयोजन के अवसर पर मध्य प्रदेश के जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय सांस्कृतिक गाँव आदिवर्त का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा आदिवर्त को मध्य प्रदेश जनजातीय एवं लोक कला राज्य संग्रहालय के रूप में परिकल्पित किया गया है। सांस्कृतिक गाँव आदिवर्त के पहले चरण में 7 जनजातियों के गाँव के परिदृश्य को शामिल किया गया है।
- आदिवर्त में प्रदेश की प्रमुख जनजातियों क्रमशः गोंड, बैगा, भील, भारिया, कोरकू, कोल एवं सहरिया के साथ पाँचों सांस्कृतिक अंचल क्रमशः बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ एवं चंबल के प्रतिनिधिक आवासों और जीवन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर प्रदर्शित किया गया है।
- संस्कृति संचालक अदिति कुमार त्रिपाठी ने बताया कि आदिवर्त संग्रहालय के माध्यम से जनजातीय कलाकारों को स्थानीय उत्पाद और पेंटिंग इत्यादि के विक्रय का बेहतर मौका मिलेगा। इससे कलाकारों की आजीविका भी सुदृढ़ होगी।

खजुराहो में 'सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी' प्रदर्शनी का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

22 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन हॉल में 'सांस्कृतिक संपत्ति की सुरक्षा और बहाली पर पोशाक खजाने की वापसी' शीर्षक वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर रि-एड्रेस रिटर्न ऑफ (ट्रेजर्स) का विमोचन भी किया गया।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 2014 से 2022 तक 229 देश से लाई गई और विरासत से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं की वापसी करवाई गई है। इनमें से चयनित वस्तुएँ प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं।
- इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत और दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत की सफल वापसी के चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से सांस्कृतिक संपत्ति के प्रत्यावर्तन की भावना, आवश्यकता और भविष्य को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शनी सांस्कृतिक वस्तुओं, उनके इतिहास और उनकी सफल वापसी के आसपास की कहानियों को दर्शाने का माध्यम बनी है।

- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान व राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रदर्शनी पुन (विज्ञापन) पोशाक खजाने की वापसी का आयोजन किया गया है।
- इस प्रदर्शनी को संस्कृति मंत्रालय ने पूरे भारत में आयोजित जी-20 के संस्कृति कार्य समूह (सीडब्ल्यूजी) की बैठकों का हिस्सा बनाया है। प्रदर्शनी में प्रदर्शित किये जा रहे सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से महिला है जिसे 2015 में कनाडा से भारत वापस लाया गया था। इसे अब खजुराहो में एएसआई साइट संग्रहालय में रखा गया है।
- प्रदर्शनी में भारत भर से लगभग 26 पुरावशेषों को चित्रित किया गया है, जो दुनिया के अन्य हिस्सों से प्रत्यावर्तन के कुछ उत्साहजनक उदाहरणों के साथ-साथ अब तक भारत लौटी पुरावशेषों की तस्वीरों और दृश्यों के साथ पूरक हैं।
- विदित है कि अब तक विभिन्न देशों से कुल 242 पुरावशेषों को भारत में प्रत्यावर्तित किया गया है। कई अन्य अभी वापसी की प्रक्रिया में हैं।
- सांस्कृतिक संपत्ति को वापस लाने की दिशा में किये गए वैश्विक प्रयास देशों के बीच सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उत्तम उदाहरण हैं। ये कला और पुरातनता के टुकड़े, अवैध तस्करी के पिछले शिकार अब सांस्कृतिक राजदूतों और सांस्कृतिक विरासत के प्रत्यावर्तन के अधिवक्ताओं के रूप में प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को करेंगी 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

23 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का शुभारंभ करेंगी। सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि और 6 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल होंगे।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन 3 से 5 मार्च, 2023 तक भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा।
- शुभारंभ-सत्र में श्रीराम जन्म-भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के स्वामी श्री गोविंददेवगिरि जी महाराज का उद्बोधन भी होगा। अतिथियों द्वारा 'द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर्स एंड थिंक्स' पुस्तक का विमोचन किया जाएगा।
- प्रथम दिवस के दूसरे-सत्र में इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग कॉउंसिल के सदस्य राम माधव की अध्यक्षता में मिनिस्टर-सत्र में भूटान, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री अपने विचार रखेंगे।
- इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालय के साथ ही अमेरिका, साउथ कोरिया, थाईलैंड, स्पेन, वियतनाम, मॉरीशस, रूस, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मंगोलिया, फ्रांस आदि देशों से आए विद्वान तथा शोधार्थी भाग लेंगे।
- विदित हो कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का आयोजन 22-23 सितंबर, 2012 को साँची विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश) में किया गया था। वहीं 6वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का आयोजन 7-9 नवंबर, 2021 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया था।

मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग को मिला केंद्र सरकार से अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के एमएसएमई के विलंबित भुगतानों के निराकरण के लिये सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल को स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्रोसिजर एवं प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये 'एमएसईएफसी एक्सिलेंस अवॉर्ड-2022' प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश के एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि को यह प्रतिष्ठापूर्ण अवॉर्ड प्रदान किया।

- एमएसएमई विभाग के सचिव और उद्योग आयुक्त पी. नरहरि ने बताया कि 1 जनवरी, 2022 से दिसंबर 2022 तक काउंसिल की 19 बैठकें हुईं, जिनमें कुल 472 प्रकरणों में सुनवाई की गई और 303 प्रकरणों में अंतिम निर्णय कर विभागीय पोर्टल में अपलोड किये गए। अर्वाइड एवं सुलह के माध्यम से तीस करोड़ 51 लाख 30 हजार 571 रुपए का भुगतान कराया गया।
- विदित है कि काउंसिल की बैठक प्रत्येक प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को की जाती है और उभयपक्षों को वर्चुअल सुनवाई की सुविधा भी दी जाती है।
- पी. नरहरि ने बताया कि केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 से 23 तक सप्लायर को यह अधिकार होता है कि यदि उसने क्रेता को सामग्री/सेवा प्रदाय की है तो नियत दिनांक से 45 दिवस के पूर्व क्रेता को भुगतान करना आवश्यक है।
- यदि समयवधि में भुगतान नहीं होता है तो सप्लायर अधिनियम के अंतर्गत क्रेता से मूलधन के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि मासिक ब्याज पाने का दावा अधिनियम की धारा 18 में कर सकता है।

प्रदेश की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को मिला प्रमाणीकरण

चर्चा में क्यों ?

24 फरवरी, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये निरंतर सक्रिय है और इसी क्रम में 'लक्ष्य' अभियान के अंतर्गत राज्य की 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य की इन 111 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं को एक लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त होगा। इस राशि को ऑपरेशन थियेटर और प्रसव कक्षों की देख-भाल तथा बेहतरी के लिये व्यय किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक और उपलब्धि प्राप्त की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिये शुरू किये गए 'लक्ष्य' अभियान में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय दल द्वारा 'लक्ष्य' अभियान में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देख-भाल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के चिकित्सालयों में उपलब्ध व्यवस्थाओं की जाँच की गई थी।

मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023

चर्चा में क्यों ?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश, 2023 के स्थान पर मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अधिनियम, 2023 को प्रतिस्थापित किये जाने के संदर्भ में निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा निवेश आशय प्रस्ताव का आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में नोडल एजेंसी को किया जाएगा।
- नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण प्राप्त निवेश आशय प्रस्ताव की अभिस्वीकृति निर्धारित प्रारूप में जारी की जाएगी।
- एमपी इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल को नोडल एजेंसी नामांकित किया गया है, जो अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।
- औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में उद्योग स्थापना के संबंध में प्राप्त की जाने वाली विनिर्दिष्ट सेवा, अनुमति, अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र प्राप्ति दिनांक से 3 साल अथवा औद्योगिक उपक्रम या औद्योगिक इकाई के व्यवसायिक गतिविधि संचालन प्रारंभ किये जाने तक जो भी पहले हो, उन्मुक्त रहेगा। उक्त अवधि समाप्त होने के 6 माह के अंदर आवश्यक अनुमतियाँ, सम्मतियाँ प्राप्त करेगा।

- जारी अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि में कोई सक्षम प्राधिकारी अधिनियम में वर्णित अनुमतियों के संबंध में निरीक्षण नहीं कर सकेगा।
- इस अधिनियम में राज्य के पास अधिसूचित क्षेत्रों का चयन करने के प्रावधान होंगे जहाँ यह अधिनियम लागू किया जाएगा।
- इकाई के प्रारंभ होने के पूर्व इकाई द्वारा आवेदन किये जाने पर संबंधित विभाग अथवा एजेंसी द्वारा आवश्यक होने पर निरीक्षण कर अनुमति एवं सहमति दी जा सकेगी।
- राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन कर सकेगी। समिति सक्षम प्राधिकारी एवं औद्योगिक उपक्रमों के साथ समन्वय कर विवाद का मैत्रीपूर्ण हल निकालेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023 का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

25 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, आर्थिक स्वालंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाए रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने के लिये 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना-2023' का अनुमोदन किया।

प्रमुख बिंदु

- योजना में समय-सीमा में स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की 23 से 60 वर्ष आयु के मध्य की विवाहित महिलाओं को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंकड बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में यदि प्रतिमाह 1000 रुपए से कम राशि प्राप्त हो रही होगी, तो उस महिला को वह राशि प्रदाय कर 1000 रुपए तक राशि की पूर्ति करने का योजना में प्रावधान किया गया है।
- योजना में समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाइन प्राप्त किये जाएंगे। इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर 'आवेदन के लिये आवश्यक जानकारी का प्रपत्र' देती है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर करने की व्यवस्था की गई है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रुपए प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जाएगी।

हलमा की परंपरा

चर्चा में क्यों ?

26 फरवरी, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ जिले के हाथीपाव पहाड़ी पर हलमा उत्सव और विकास यात्रा के समापन समारोह में कहा कि हलमा की परंपरा को समूचे मध्य प्रदेश में विस्तारित किया जायेगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि हलमा ऐसी परंपरा है, जिससे प्रकृति को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया जा सकता है। वनवासी समाज की हलमा परंपरा अद्वितीय है। यह संकट में खड़े मनुष्य की सहायता का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि इस परंपरा को समूचे मध्य प्रदेश में विस्तारित करते हुए जल, मिट्टी और पर्यावरण-संरक्षण का कार्य किया जाएगा।
- भारत के जनजाति समाज में आज भी जीवन यापन की कई देशज विधाएँ मौजूद हैं जो वर्तमान समय में विकास के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। उन्हीं में से एक विधा है भील जनजाति की हलमा परंपरा। इस परंपरा के महत्त्व के कारण ही 24 अप्रैल, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसका जिक्र किया।

- हलमा ने झाबुआ जिले के बड़े हिस्से में जल संकट को कम करने में बड़ी भूमिका निभाई है। भील समुदाय की यह परंपरा देशज विधाओं की तकनीकी समृद्धता का अनोखा उदाहरण है।
- आदिवासी जनजातियों में हलमा हाँडा और हीडा जैसे नामों से परस्पर सामुदायिक सहयोग की भावना की इस तरह की प्रथा या परंपरा मौजूद हैं और लोक साहित्य में इनका उल्लेख भी है। परंतु कालांतर में ये लुप्त होती गई।
- गौरतलब है कि हलमा भील समाज में एक मदद की परंपरा है। जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बाद भी अपने पर आए संकट से उबर नहीं पाता है तब उसकी मदद के लिये सभी ग्रामीण भाई-बंधु जुटते हैं और अपने निःस्वार्थ प्रयत्नों से उसे मुश्किल से बाहर ले आते हैं।
- यह एक ऐसी गहरी और उदार परंपरा है जिसमें संकट में फँसे व्यक्ति की सहायता तो की जाती है पर दोनों ही पक्षों द्वारा किसी भी तरह का अहसान न तो जताया जाता है न ही माना जाता है। परस्पर सहयोग और सहारे की यह परंपरा दर्शाती है कि समाज में एक दूजे की मजबूती कैसे बना जाता है। किसी को भी मझधार में अकेले नहीं छोड़ा जाता है बल्कि उसे निश्चल मदद के द्वारा समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है।
- भील शब्द का महत्त्व इसीलिये भी अधिक हो जाता है क्योंकि इस जनजाति को भारत की सबसे प्राचीन और अपनी परंपराओं को जीवित रखने वाली जनजाति माना जाता है। भील भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समाज है। आजादी से पहले हुए अंतिम जनगणना 1941 के अनुसार देश में भीलों की आबादी लगभग 2 मिलियन थी जो अब 17 मिलियन हो चुकी है।
- भील समुदाय मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश के अन्य राज्यों में भी हैं। मध्य प्रदेश का भील समुदाय अन्य भील समुदाय के जैसे ही अपनी परंपरा को जीवित रखे हुए है। आज भी मध्य प्रदेश के भीलों की सांस्कृतिक परंपरा उनके धार्मिक कृत्यों, उनके गानों तथा नृत्यों, उनके सामुदायिक देवी-देवताओं, त्वचा के गोदनों, पौराणिक गाथाओं तथा विधा में अभिव्यक्त होती है। उनके घरों से सौंदर्यशास्त्र का सहज बोध प्रकट होता है।
- उल्लेखनीय है कि सन 2005 में हलमा परंपरा को एक गैर-सरकारी संगठन 'शिवगंगा' ने शुरू किया। महेश शर्मा और हर्ष चौहान की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। महेश शर्मा को भारत सरकार द्वारा उनके कार्यों के लिये 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आज वो भील जनजातियों के बीच झाबुआ के गांधी बन चुके हैं।
- हलमा को बड़े पैमाने पर 2008 में व्यावहारिक रूप दिया गया। परिणामस्वरूप साल 2009 के पहले हलमा में पानी के छोटे-छोटे गड्ढे बनाने के लिये आठ सौ लोग सामने आए और श्रम दान किया, अगले वर्ष यानि 2010 में सहभागिता बढ़कर 1600 हो गई। 2011 में दस हज़ार लोग इसमें शामिल हुए और आज यह संख्या एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसे देखने और समझने के लिये सरकार से लेकर शोधार्थियों की बड़ी संख्या इस पर शोध कर रही है। साथ ही बाहरी दुनिया से बढ़ते संपर्क ने इस क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों से अपनी समस्या के समाधान का तरीका भी सिखाया है।

जलवायु परिवर्तन और वन-संरक्षण के लिये डब्ल्यू.आर.आई. और एफ़ो में हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

27 फरवरी, 2023 को जलवायु परिवर्तन पर आयोजित कार्यशाला में पर्यावरण विभाग के एफ़ो और अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान डब्ल्यूआरआई इंडिया के बीच प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर तकनीकी सहयोग के लिये एमओयू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नवंबर 2022 में मिस्त्र में संपन्न जलवायु परिवर्तन सम्मलेन सीओपी-27 के मुख्य बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण कर विचार-विमर्श किया जाना था।
- कार्यपालन संचालक एफ़ो मुजीबुर्हमान खान ने कहा कि एमओयू अगले 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन एवं वनों के संरक्षण संबंधी कार्य पर केंद्रित होगा। इन वर्षों में उपयोगी एवं सार्थक प्रयास किये जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप हम सस्टेनेबल और ग्रीन डेवलेपमेंट की ओर परस्पर ठोस कदम बढ़ाएंगे।

- एफ्को, राज्य एवं जिला स्तर पर डब्ल्यूआरआई इंडिया और संबंधित विभागों को समस्त प्रकार की संस्थागत एवं तकनीकी सहायता देना जारी रखेगा।
- राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के समन्वयक लोकेंद्र ठक्कर ने कहा कि एफ्को म.प्र. शासन की विशिष्ट संस्था है, जो राज्य शासन को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के साथ शोध अध्ययन, योजना कार्य तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास के कार्यों के लिये प्रतिबद्ध है।
- कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीएन इंटरनेशनल के हेड हरजीत सिंह ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित Loss & Damage विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन के कृषि, जल-संसाधन, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्रों में एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील राज्य है। उपयुक्त नीतियों के साथ तकनीकी और वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता स्थानीय स्तर के समाधानों को बढ़ाने, लचीला बनाने और हानियों एवं क्षतियों को दूर कर मानव क्षमता बढ़ाने के लिये आवश्यक है।
- डब्ल्यूआरआई इंडिया के क्लाइमेट प्रोग्राम की निदेशक उल्का केलकर ने कहा कि भारत में क्लाइमेट एक्शन के मामले में मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत के शीर्ष 10 राज्य में से एक है।
- राज्य, आर्द्र-भूमि की रक्षा, पारंपरिक जल-संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवित करने और देशी मवेशियों की नस्लों को बढ़ावा देने जैसे उपायों को लागू कर रहा है। प्रदेश के बड़े और छोटे शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन का हिस्सा बनने समुदायों के लिये भी काफी संभावनाएँ हैं।

दृष्टि
The Vision